भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2560
11.08.2025 को उत्तर देने के लिए

देश में आय असमानता संबंधी आंकड़े

2560. श्री संदोष कुमार पीः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में आय संबंधी असमानता के बारे में नवीनतम राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में गरीबी में कमी आने का कोई प्रमाण हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क): आय असमानता संबंधी डेटा केंद्र सरकार द्वारा संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ख) से (घ): वर्ष 2021 में, भारत सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे आयामों में अतिव्यापी विचलनों को कैप्चर करके गरीबी के आकलन के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) नामक एक व्यापक सूचकांक विकसित किया है, जिसमें 12 संकेतक शामिल हैं। यह गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या तथा उनकी वंचितता की सीमा, दोनों को मापता है। सूचकांक का दूसरा संस्करण वर्ष 2023 में जारी किया गया था। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, वर्ष 2015-16 और वर्ष 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का अनुपात 24.85% से घटकर 14.96% हो गया, जो यह दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान लगभग 135.5 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित परिचर्चा पत्र 'वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी' के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% हो गया है, जो यह दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह सतत विकास लक्ष्य 1.2 के प्रयोजन को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा योगदान है, जिसका उद्देश्य "राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार गरीबी के सभी आयामों में रहने वाले सभी आयु वर्ग के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम से कम आधा करना" है।

*****